vkj- ,u- vkb- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- iath;u- l[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"kZ % 15 vad % 15 y[kuÅ] jfookj 21 tqykbZ 2024 ls 27 tqykbZ 2024 rd i"B&8 ewY; % ,d :i;k

विश्व धरोहर समिति के ४६वें सत्र की मेजबानी के लिए तैयार भारत, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी २१ जुलाई २०२४ को शाम ७ बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के ४६वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। उद्घाटन समारोह में यूनेस्को की महानिदेशक अ ड्रे अजोले भी शामिल होंगी। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। यह २१ से ३१ जुलाई, २०२४ तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। जानकारी के मुताबिक विश्व धरोहर समिति की साल में एक बार बैठक होती है और यह विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इस बैठक के दौरान, विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने, १२४ मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधि के उपयोग आदि के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में १५० से अधिक देशों के २००० से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे।

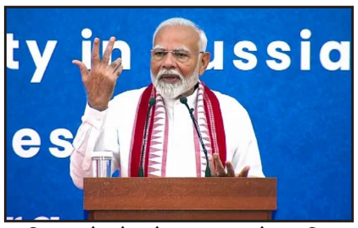

विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ–साथ, विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच और विश्व धरोहर स्थल प्रबंधक मंच भी किनारे पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए भारत मंडपम में विभिन्न प्रदर्शनियाँ भी स्थापित की जाएंगी। रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स प्रदर्शनी में देश में वापस लाई गई कुछ कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। अब तक ३५० से अधिक कलोतियाँ वापस लायी जा चुकी हैं। इसके अलावा, नवीनतम एआर और वीआर प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, भारत के ३ विश्व धरोहर स्थलों के लिए एक गहन अनुभव की पेशकश की जाएगीरू रानी की वाव, पाटन, गुजरातय कैलासा मंदिर, एलोरा गुफाएँ, महाराष्ट्रय और होयसला मंदिर, हलेबिड, कर्नाटक। साथ ही, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सदियों पुरानी सभ्यता, भौगोलिक विविधता, पर्यटन स्थलों के साथ–साथ सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आधुनिक विकास को उजागर करने के लिए एक 'अतुल्य भारत' प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

NEET पेपर लीकः CBI को मिली बड़ी सफलता, दो मेडिकल छात्र समेत ३ को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। नीट विवाद मामले में सीबीआई ने 'मास्टरमाइंड' एक बीटेक ग्रेजुएट और दो एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने 'सॉल्वर' के रूप में काम किया था। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सीबीआई ने पटना में भरतपुर मेडिकल कॉलेज के दो मेडिकल छात्रों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मेडिकल छात्रों की पहचान कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। तकनीकी निगरानी ने परीक्षा के दिन हजारीबाग में उनकी उपस्थिति की पुष्टि की है। गिरफ्तार किया गया दूसरा व्यक्ति, शशि कुमार पासवान, एक 'ऑलराउंडर' है। वह सरगना को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा था। इसके अलावा शशि कुमार पासवान नीट पेपर लीक मामले का भी सरगना है. वह पहले गिरफ्तार किये गये पंकज उर्फ आदित्य का साथी है और उसने उसे हजारीबाग से ट्रंक से पेपर चुराने में मदद की थी. जानकारी के मुताबिक, ये सभी परीक्षा के दिन ५ मई की सुबह पेपर सॉल्व करने के लिए हजारीबाग में मौजूद थे। वहीं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा–स्नातक (नीट–यूजी) के केंद्रवार और शहरवार परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए। यह परीक्षा कथित अनियमितताओं को लेकर

जांच के घेरे में है। नीट–यूजी के परिणाम पांच जून को घोषित किए गए थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इन्हें इस प्रारूप में प्रकाशित किया गया है। उच्चतम न्यायालय प्रश्नपत्र लीक सहित परीक्षा कराने में कथित अनियमितताओं के संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अभ्यर्थियों की पहचान उजागर नहीं करते हुए परिणाम घोषित किए जाएं। उसने कहा था कि वह यह पता लगाना चाहता है कि कथित विवादित केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अन्य स्थानों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक तो नहीं मिले हैं।

मुख्यमंत्री योगी के फैसले के साथ मजबूती से खड़े हुए केशव प्रसाद मौर्य, विपक्ष को खूब सुनाया

लखनऊ। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के फैसले की खूब आलोचना हो रही है। विपक्ष के साथ–साथ भाजपा की कई सहयोगी दल भी योगी सरकार के फैसले के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपनी सरकार के फैसले के साथ हम मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का यह रुख तब आया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी दूरियों को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चाओं का दौर जारी है। कांवड़ यात्रा और नेम प्लेट को लेकर जारी विवाद को केशव प्रसाद मौर्य ने खारिज किया और कहा कि इसका विरोध वे लोग कर रहे हैं जिन्हें मुस्लिम वोट की जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा कि विपक्ष को भी कांवड़ लेकर (हरिद्वार) जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए ताकि उनकी बुद्धि में जो विंति आई है वह ठीक हो सके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, वे केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, करते हैं कोई अन्य उद्देश्य या विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर

'नेमप्लेट' लगाने के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार अगर तत्कालीन कोई विज्ञप्ति निकालती है तो सभी को मानना होता है। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा कि कांवरियों को यह जानने का अधिकार है कि वे कहां से सामान खरीद रहे हैं। यह अधिसूचना मुलायम सिंह यादव सरकार और मायावती सरकार द्वारा पारित की गई थी...यह कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं है। वहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, जयंत चौधरी की रालोद के बाद अब चिराग की पार्टी की बारी है। चिराग ने मुजफ्फरनगर में पुलिस की उस सलाह पर आपत्ति जताई है, जिसमें भोजनालयों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। चिराग पासवान ने कहा कि वह पुलिस की सलाह या 'जाति या धर्म के नाम पर विभाजन' पैदा करने वाली किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह सलाह का समर्थन करते हैं', लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष ने कहा, 'नहीं, मैं नहीं करता।' खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले पासवान ने कहा कि उनका मानना है कि समाज में दो वर्ग के लोग मौजूद हैं — अमीर और गरीब — और विभिन्न जातियों और धर्मों के व्यक्ति दोनों श्रेणियों में आते हैं।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदन का सत्र २६ जुलाई से शुरू होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र २६ जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र कब तक चलेगा अभी इसकी घोषणा नहीं की गयी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे और विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह ने यह जानकारी दी। दोनों प्रमुख सचिवों ने जारी अधिसूचना में कहा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद की बैठक को २६ जुलाई से आहूत किया है। बयान में कहा गया, ''राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अठारहवीं विधानसभा के वर्ष २०२४ के दूसरे सत्र के लिए सोमवार, २६ जुलाई, २०२४ को पूर्वाह्न ११ बजे विधान भवन, लखनऊ के विधान सभा मंडप में बैठक के लिए बुलाया है।'' हाल में हुए आम चुनावों के बाद उप्र विधानमंडल का यह सत्र शुरू होने जा रहा है। उप्र की १८वीं विधानसभा के गठन के बाद उप्र में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव निभाते रहे हैं

लेकिन उनके लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद चुने जाने और विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिये जाने के बाद से उप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त है। संभावना जतायी जा रही है कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी शीघ्र ही नये नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है।

सम्पादकीय

मुंगेरीलाल के हसीन सपने 2027 में 47 पर समेटेंगे

इसमें कोई दोराय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि विपक्ष भी इसके मजे ले रहा है। इन सब के बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने म नसून अ फर दिया था जिसमें कहा गया था कि १०० विध ायक लाओ और सरकार बनाओ। अब इसी पर केशव मौर्य ने पलटवार किया है। मौर्य ने इसे मुंगेरीलाल के हसीन सपने बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पोस्ट में दावा किया कि म नसून अ फर को २०२७ में ४७ पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। बिना नाम लिए केशव मौर्य ने सपा को डूबता जहाज बताया। उन्होंने कहा कि एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खघ्तरे में है। वह मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि २०२७ में २०१७ दोहरायेंगे, फिर कमल की सरकार बनायेंगे। अखिलेश की ओर से यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर बढ़ते तनाव के बीच आया है। यादव की टिप्पणी का उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी मौर्य के बीच कथित दरार को भुनाना था। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफ र्म एक्स पर यूपी के उपमुख्यमंत्री मौर्य ने अखिलेश पर तंज कसते हुए उन्हें एसपी श्बहादुरश कहा और कहा कि बीजेपी के पास देश और प्रदेश दोनों में एक मजबूत संगठन और सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने सपा के पीडीए फ र्मूले (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्याक) पर निशाना साधते हुए इसे धोखा बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का च्क। धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है, भाजपा २०२७ विधानसभा चुनाव में २०१७ दोहरायेगी। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर चर्चा के बीच, मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के भीतर अंदरूनी कलह से तंग आ चुकी है। यह उपमुख्यमंत्री की एक टिप्पणी की पृष्ठभूमि में आया है जिससे अटकलें लगाई जाने लगीं कि उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। हालाँकि, भाजपा ने इस चर्चा को खारिज कर दिया है। अखिलेश ने एक्स पोस्ट पर लिखा था कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में, उप्र में शासन–प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचनेवाला भाजपा में कोई नहीं है।

मुख्यमंत्री योगी का फैसला, कांवड़ रूट की हर दुकान पर लगाना होगा नेमप्लेट और लिखना होगा मालिक का नाम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कांवर यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया। यह निर्णय विपक्षी दलों के विरोध के बाद मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा अपने आदेशों को रद्द करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें भोजनालयों के लिए मालिकों के नाम प्रदर्शित करना 'स्वैच्छिक' हो गया है। निर्देश के मुताबिक, हर खाने–पीने की दुकान या ठेले वाले को बोर्ड पर मालिक का नाम लिखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय कांवर यात्रियों की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया है। अब, हर भोजनालय, चाहे वह रेस्तरां हो, सड़क किनारे ढाबा हो, या यहां तक कि खाने की गाड़ी भी हो, उसे मालिक का नाम प्रदर्शित

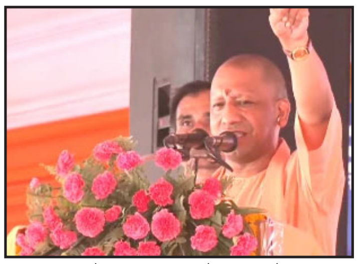

करना होगा। इससे पहले आज उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आरोप लगाया कि मुस्लिम, हिंदू नामों की आड़ में तीर्थयात्रियों को मांसाहारी भोजन बेचते हैं। मंत्री ने कहा, 'वे वैष्णो ढाबा भंडार, शाकुंभरी देवी भोजनालय और शुद्ध भोजनालय जैसे नाम लिखते हैं और मांसाहारी भोजन बेचते हैं।' २२ जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं। इस बीच, उत्तराखंड पुलिस ने भी निर्देश जारी कर कांवड़ यात्रा मार्गों पर भोजनालयों को बोर्ड पर मालिकों के नाम लिखने को कहा है। मीडिया से बात करते हुए, हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रमोद सिंह डोबाल ने कहा, 'होटल, ढाबा या स्ट्रीट फूड स्टॉल संचालित करने वाले सभी लोगों को अपने प्रतिष्ठान पर मालिक का नाम, क्यूआर कोड और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया है। इसका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कांवर मार्ग से भी हटा दिया जाएगा।''

लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, में एससीआर की तर्ज पर यूपी में होगा एनसीआर का गठन

लखनऊ,। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की जिसमें दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के पांच अन्य जिले शामिल होंगे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आधिकारिक तौर पर लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया। रिपोर्ट के अनुसार, नवगठित एससीआर में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिले शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल २७,८२६ वर्ग किमी है। सितंबर २०२२ में इस परियोजना की शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी शामिल हैं, जिसका गठन राजधानी शहर पर जनसंख्या के दबाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राज्य की राजधानी और आसपास के जिलों में बढ़ती आबादी के कारण अनियोजित विकास की शिकायतों पर जोर है। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक ये फैसले विकास के लिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं। २०११ की जनगणना के अनुसार, लखनऊ की जनसंख्या ४,५८६,८३८ है, बारदोई की जनसंख्या ४,०९२,८४५ है, सीतापुर की जनसंख्या ४, ४८३, ६६२ है, उन्नाव की जनसंख्या ३, १०८, ३६७ है, रायबरेली की जनसंख्या ३,४०५, ५५६ है और बाराबंकी की जनसंख्या ३,२६०,६६६ है। ६ जिलों को मिलाकर एससीआर

की आबादी करीब २३ लाख होगी। २०११ की संख्या के अनुसार, लखनऊ का जनसंख्या घनत्व १८१६ प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के जनसंख्या घनत्व (८२६ प्रति वर्ग किलोमीटर) से दोगुने से भी अधिक है। लखनऊ का जनसंख्या घनत्व ३६७१ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के साथ गाजियाबाद (दिल्ली एनसीआर का हिस्सा) और २३६५ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के साथ वाराणसी के बाद राज्य में तीसरा सबसे अधिक है। विभिन्न शहरों से लोग यहां आकर अपना स्थायी निवास बनाना चाहते हैं। आसपास के जिलों में जनसंख्या का दबाव भी बढ़ रहा है और कई बार अनियोजित विकास की शिकायतें भी मिलती रहती हैं। राष्ट्रीय राजध ानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अधिसूचित एनसीआर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र–दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को कवर करता है, जो लगभग ५५,०८३ वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है। १९५१–६१, १९६१–७१, १९७१–८१ और १९९१–०१ दशकों के दौरान दिल्ली की जनसंख्या वृद्धि दर ५२.४४ः, ५२.९१ः, ५२.९८ः, ५१.४५ः और ४७.०३ः थी, जिसका कारण निकटवर्ती क्षेत्रों से दिल्ली आने वाले प्रवासियों में वृद्धि थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, राज्यों में भीड़भाड़ और नागरिक सुविधाओं की कमी है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, इससे भीड़भाड़ और सुविधाओं की कमी ने ष्क्षेत्रीय संदर्भ में दिल्ली की योजना बनाना' अनिवार्य बना दिया।

'एक पेड़ मां के नाम' अकबरनगर को हटाकर सौमित्र वन स्थापित किया जा रहा : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधे लगाने का अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ५ जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। दुनिया

में ग्लोबल वार्मिंग एक नया संकट बनता जा रहा है और इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही होनी चाहिए और इसी क्रम में प्रध ानमंत्री मोदी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए एक मंत्र बनना चाहिए और इस अभिलाषा से हमने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ५० साल पहले ये कुकरैल नदी होती थी लेकिन १९८४ के बाद पूरी नदी को भू–माफियाओं ने पाटना शुरू किया और परिमाण क्या हुआ? जो कभी नदी थी वो नाला बन गया. ..इसकी वजह से गोमती नदी भी प्रदूषित हो गई...गोमती नदी काली हो गई। सरकार ने तय किया है कि लखनऊ में आने वाले पर्यटकों, प्रदेशवासियों के लिए हम कुकरैल क्षेत्र में नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। सीएम ने कहा कि हम कुकरैल क्षेत्र को विकसित करेंगे...इस क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाकर, जिन लोगों ने यहां रजिस्ट्री की थी, उनको आवास उपलब्ध कराए गए। जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भू–माफिया बनकर लोगों को ठगने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनपर एफआईआर दर्ज कराई गई और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है।

स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी संघमित्रा भगोड़ा घोषित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को बेटी संघमित्रा मौर्य के साथ भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। लखनऊ की एमपी–एमएलए कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी, बदायूं से पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य और तीन अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की ध ारा ८२ के तहत आदेश जारी किया है। एसीजेएम तृतीय एमपी–एमएलए आलोक वर्मा की अदालत ने यह कदम तब उठाया जब मौर्य समेत अन्य आरोपी तीन समन, दो जमानती वारंट और एक गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इस विवादास्पद मामले में पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और पूर्व भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य शामिल हैं। इससे पहले मौर्य परिवार ने इस मामले में एमपी–एमएलए कोर्ट के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, जस्टिस जसप्रीत सिंह की अदालत ने मौर्य को फटकार लगाते हुए कहा, श्आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, आपको एमपी–एमएलए कोर्ट में वापस आना होगा।श् इसके बावजूद मौर्य परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां उनकी याचिका को गंभीरता से नहीं लिया गया। वादी दीपक कुमार स्वर्णकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता रोहित कुमार त्रिपाठी और राजेश कुमार तिवारी ने अदालत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, ष्हमें विश्वास है कि न्याय तुरंत मिलेगा।'

ना संगठन ना सरकार, सबसे बड़ा होता है जन कल्याण : अखिलेश यादव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सियासत जबरदस्त तरीके से जारी है। भाजपा में उठापटक की स्थिति है और सपा भगवा पार्टी में फूट का आनंद लेने की कोशिश में है। वही, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वार–पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। आज केशव प्रसाद ने अखिलेश के मानसून अ फर पर जवाब दिया। इसके बाद एक बार फिर से अखिलेश ने केशव मैर्य पर पलटवार किया है। अखिलेश ने एक्स पोस्ट में कहा कि न संगठन बड़ा होता है, न सरकार। सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। सपा नेता ने आगे कहा कि दरअसल संगठन और सरकार तो बस साधन होते हैं, लोकतंत्र में साध्य तो जनसेवा ही होती है। जो साधन की श्रेष्ठता के झगड़े में उलझे हैं, वो सत्ता और पद के भोग के लालच में है, उन्हें जनता की कोई परवाह ही नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपाई सत्तान्मुखी है, सेवान्मुखी नहीं! अखिलेश यादव ने म नसून ऑफर दिया था जिसमें कहा गया था कि १०० विधायक लाओ और सरकार बनाओ। अब इसी पर केशव मौर्य ने पलटवार किया है। मौर्य ने इसे मुंगेरीलाल के हसीन सपने बताया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पोस्ट में दावा किया कि म नसून अ फर

को २०२७ में ४७ पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। बिना नाम लिए केशव मौर्य ने सपा को डूबता जहाज बताया। उन्होंने कहा कि एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खघ्तरे में है। वह मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि २०२७ में २०१७ दोहरायेंगे, फिर कमल की सरकार बनायेंगे। अखिलेश की ओर से यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में भाजपा के भीतर बढ़ते तनाव के बीच आया है। यादव की टिप्पणी का उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी मौर्य के बीच कथित दरार को भुनाना था। इससे पहले मौर्य ने भी अपने एक बयान में सरकार से ज्यादा पार्टी संगठन की प्रधानता पर जोर दिया था। भाजपा की एक दिवसीय राज्य कार्यसमिति की बैठक के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की संरचना और उसका कैडर हमेशा सरकार से अधिक महत्व रखेगा। मौर्य ने कहा कि सभी मंत्रियों, विधायकों और जन प्रतिनिधियों को पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी गरिमा बरकरार रहे। अपने भाषण में, मौर्य ने हालिया लोकसभा चुनाव परिणामों पर विचार किया और स्वीकार किया कि वे पार्टी की उम्मीदों से कमतर रहे। उन्होंने इन चुनावी असफलताओं के लिए विपक्ष द्वारा प्रचारित 'झूठ और धोखे' को जिम्मेदार ठहराया।

जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना अपराधः प्रियंका गांधी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर भोजनालयों के लिए मालिकों का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाने के निर्देश को लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष के साथ साथ भाजपा के कई सहयोगी भी योगी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने भी एक्स पोस्ट को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। कांग्रेस महासचिव ने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। उन्होंने कहा कि समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं, निर्देश जारी होने के

बाद, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने न्यायपालिका से इस कदम के पीछे ष्सरकार की मंशाष् की जांच करने के लिए मामले का स्वतरू संज्ञान लेने को कहा। अखिलेश ने लिखा और जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा? उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जाँच करवाकर, उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'सिर्फ राजनीतिक दलों को ही नहीं, सभी सही सोच वाले लोगों और मीडिया को इस राज्य प्रायोजित कट्टरता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हम भाजपा को देश को अंधेरे युग में वापस धकेलने की अनुमति नहीं दे सकते।' वर यात्रा २२ जुलाई से शुरू होने वाली है। जुलूस की तैयारी में, मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने एक आदेश जारी कर कांवर यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने मालिकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए कहा। विपक्षी दलों ने इस कदम को मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाने के रूप में देखा।

मेडिकल सीट के लिए बनाया ओबीसी सर्टिफिकेट

लखनऊ। पूजा खेडकर जिन्होंने कथित तौर पर चयनित होने के लिए फर्जी विकलांगता और जाति प्रमाण पत्र जमा किया था, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ कई आरोप सामने आने के साथ विवाद तेज हो गया है। महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी की मुश्किलें इस हफ्ते तब बढ़ गईं जब सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने वाली यूपीएससी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। विवाद शुरू होने के बाद से उनके मेडिकल प्रमाणपत्रों में कई विसंगतियां सामने आई हैं। विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय उन्होंने दो अलग–अलग नामों – खेडकर पूजा दीलीप्राओ और पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर का भी इस्तेमाल किया। खेडकर इस महीने की शुरुआत में तब सुर्खियों में आई थीं, जब परिवीक्षा अवधि के दौरान लाल बत्ती वाली निजी कार के इस्तेमाल सहित उनके अनुचित आचरण की शिकायतों को लेकर उन्हें पुणे से वाशिम जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने एक अलग कार्यालय, एक आधिकारिक वाहन और कर्मचारियों की भी मांग की – ये विशेषाधिकार प्रशिक्षु अधिकारियों को नहीं दिए जाते।

योगी सरकार के फैसले से नाराज मुस्लिम संगठन ने कहा- मदरसों को कमजोर करने की कोशिशें नहीं होगी बर्दाश्त

लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, धार्मिक और राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों और मदरसों के नेताओं ने एक संयुक्त बयान में विभिन्न राज्यों में मदरसों को कमजोर करने के प्रयासों की निंदा की है और कहा है कि उनके संस्थानों पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बयान में कहा गया है कि हम, देश के नागरिक, विभिन्न बहानों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में मदरसों की स्थिति और पहचान को कमजोर करने के प्रयासों की कड़ी निंदा करते हैं। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों यानी मदरसों के संबंध में राज्य सरकारों को जारी किए गए निर्देश अवैध हैं और आयोग के अधिकार क्षेत्र से परे हैं। यह तब आया है जब उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को मदरसों का सर्वेक्षण करने और छात्रों को ष्गैर–मान्यता प्राप्त स्कूलों' (स्वतंत्र मदरसा) से सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। ८,४४६ ष्गैर–मान्यता प्राप्त स्कूलों' स्वतंत्र मदरसों की एक सूची प्रकाशित की गई है, जिसमें दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवातुल उलेमा, लखनऊ, मजाहिर उलूम सहारनपुर, जामिया सलाफिया वाराणसी, जामिया अशरफिया मुबारकपुर, मदरसतुल इस्लाह सरायमीर, और जामिया अल फलाह बलेरियागंज जैसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक संस्थान शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट इन संस्थानों से छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुख्य सचिव का यह सर्कुलर और जिला अधिकारियों का दबाव पूरी तरह से अवैध है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इसके अतिरिक्ति, जिला प्रशासन ने गैर–मुस्लिम छात्रों को इन स्कूलों

से हटाकर सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया है, जो उनके चुनने के व्यक्तिगत अधिकार और हमारी संयुक्त भारतीय संस्कृत और सभ्यता पर हमला है। अब मुस्लिम छात्रों पर भी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बुनियादी शिक्षा हासिल करने का दबाव डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि अनुपालन न करने की स्थिति में इन मदरसों के प्रशासकों को कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए मदरसों में छात्रों को प्रतिदिन सरस्वती वंदना करने के लिए बाध्य किया है। संयुक्त बयान में कहा गया है.हम, मुस्लिम धार्मिक और राष्ट्रीय संगठनों के जिम्मेदार सदस्य, और धार्मिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों के प्रमुख, यह स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि संविधान के अनुच्छेद ३०(१) के तहत, अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का मौलिक अधिकार है।

गोंडा रेल हादसाः मरने वालों की संख्या ४ पहुंची

गोंडा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गुरुवार को चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक ट्रेन के कुछ डिब्बों के पटरी से उतर जाने से मरने वालों की संख्या अब चार हो गई है। कई अन्य अभी भी जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटनास्थल पर कोच के नीचे से एक और शव बरामद हुआ। हालांकि उसकी अभी पहचान नहीं हो सकी है। इस प्रकार मौत का कुल आंकड़ा चार हो गया है। एक अधिकारी ने बताया कि वैगन कीचड़ में पलटा पड़ा था। क्रेन द्वारा वैगन को उठाने के बाद शव बरामद किया गया गया। अभी तक दो लोगों को लखनऊ में भर्ती कराया गया है। एक खतरे से बाहर है। अभी एक मरीज गंभीर रूप से घायल है। चार लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास गुरुवार को चंडीगढ़–डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण बड़ा हादसा हुआ ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेकर स्थानीय प्रशासन को प्रभावित यात्रियों की हर संभव मदद का निर्देश दिया है। उन्होंने

अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि घायलों को सही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। दुर्घटनास्थल राजधानी लखनऊ से करीब १५० किलोमीटर दूर है। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीणों ने पलटे एसी कोच के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। कुछ ही देर में एसडीआरएफ, पुलिस व आरपीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया।

यूपीएससी अध्यक्ष मनोज सोनी ने ''निजी कारणों'' का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया

नयी दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष मनोज सोनी ने ''निजी कारणों'' का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सोनी का कार्यकाल मई २०२६ में समाप्त होना था। सूत्रों ने कहा कि सोनी के इस्तीफे का परिवीक्षाधीन आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी पूजा खेडकर का मामला सामने आने के बाद ''संघ लोक सेवा आयोग पर उठ रहे सवालों से कोई लेना–देना नहीं है।'' एक सूत्र ने कहा, ''यूपीएससी अध्यक्ष ने निजी कारणों का हवाला देते हुए एक पखवाड़े पहले इस्तीफा सौंप दिया था। इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।'' प्रख्यात शिक्षाविद् सोनी (५९) ने २८ जून, २०१७ को आयोग के सदस्य के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने १६ मई, २०२३ को यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी और उनका कार्यकाल १५ मई, २०२६ को समाप्त होना था। सूत्रों के मुताबिक, सोनी यूपीएससी अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था, लेकिन तब उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि सोनी अब ''सामाजिक–धार्मिक गतिविधियों'' पर अधिक समय देना चाहते हैं। यह घटनाक्रम इसलिए महत्व रखता है, क्योंकि यूपीएससी ने कहा था कि उसने परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की हैं, जिनमें फर्जी पहचान दस्तावेज के जरिये सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के अधिक मौके पाने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराना शामिल है। आयोग ने कदाचार के आरोपों की 'गहन जांच' के बाद खेडकर के खिलाफ

आपराधिक मामला दर्ज कराया। उसने सिविल सेवा परीक्षा–२०२२ के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। खेडकर द्वारा सत्ता और विशेषाधिकारों के कथित दुरुपयोग का मामला जब से सामने आया है, तब से सोशल मीडिया पर आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल के दावों और प्रतिदावों की बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम, तस्वीरें और अन्य विवरण साझा किए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर–क्रीमी लेयर) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित लोगों के लिए उपलब्ध लाभों का दावा करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। यूपीएससी में अपनी नियुक्ति से पहले सोनी ने कुलपति के रूप में तीन कार्यकाल पूरे किए थे। उन्होंने एक अगस्त २००९ से ३१ जुलाई २०१५ तक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (बीएओयू), गुजरात के कुलपति के रूप में लगातार दो कार्यकाल और अप्रैल २००५ से अप्रैल २००८ तक बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय (एमएसयू) के कुलपति के रूप में एक कार्यकाल पूरा किया। एमएसयू में नियुक्त होने के दौरान सोनी भारत में किसी विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं राजनीति विज्ञान के विद्वान सोनी सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू), वल्लभ विद्यानगर में अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय पढ़ाया करते थे। यूपीएससी का नेतृत्व अध्यक्ष करता है और इसमें अधिकतम १० सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में यूपीएससी में सात सदस्य हैं, जो इसकी स्वीकृत संख्या से तीन कम हैं।

यूपी सरकार के आदेश का सहयोगियों ने किया विरोध

नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले दुकानों में दुकानदारों के नाम लिखने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियो के साथ साथ अब भाजपा की सहयोगी पार्टियों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकानों पर बड़े अक्षरों में मालिकों का नाम लिखना होगा। माना जा रहा है कि मुसलमानों की पहचान के लिए यह आदेश दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के खिलाफ भाजपा की तीन सहयोगियों पार्टियां खुल कर सामने आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल और बिहार की दो सहयोगी पार्टियों, जनता दल यू और लोक जनशक्ति पार्टी ने इसका विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने इस आदेश का विरोध किया है और कहा है कि इससे एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। इसी तरह केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के आदेश पर कहा कि वे फैसले का समर्थन नहीं करते। जाति या धर्म के नाम पर किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते हैं। समाज में सिर्फ दो वर्ग अमीर और गरीब हैं। विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग इसी दोनों श्रेणियों में आते हैं। जनता दल यू के महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी

ने कहा– इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। पीएम मोदी की जो व्याख्या भारतीय समाज, एनडीए के बारे में है, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास', यह प्रतिबंध इस नियम के खिलाफ है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कहा– यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। यह प्रयास धर्म विशेष के लोगों का आर्थिक बायकट करने का है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा– यह अव्यावहारिक कार्य है। इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए।

नर्सेस एसोसिएशन का आरोप करोड़ों का नुकसान करा रहे जिम्मेदार

लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की नर्सेस एसोसिएशन ने गंभीर आरोप लगाया है। यह आरोप केजीएमयू के जिम्मेदार अधिकारियों पर लगाया गया है। कुलपति और कुलसचिव को पत्र लिखकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। केजीएमयू नर्सेस एसोसिएशन की तरफ से भेजे गये पत्र में ८ से अधिक समस्या का जिक्र किया गया है। जिसमें सबसे गंभीर आरोप यह है कि नवनियुक्त नर्सिंग आफिसर की ट्रेनिंग के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। पत्र में लिखा है कि नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को ३ माह तक मेडिकल क लेज में सैर कराने एवं काम न करने का आदेश देकर करोड़ों के सरकारी राजस्व का नुकसान किया गया है। दरअसल, केजीएमयू में १२४६ नर्सिंग अ फिसरों का चयन हुआ था। इन्हीं नर्सिंग ऑफिसरों को बेहतर कार्य के लिए इंडक्शन प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग कराई गई थी। जिसके पीछे केजीएमयू के कुलपति की मंशा थी कि नवनियुक्त नर्सिंग ऑफिसर को उनके कार्य और भूमिका से परिचित कराया जाये। साथ ही प्रशिक्षण देकर मरीजों को गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराया जा सके। बताया जा रहा है कि इसी प्रशिक्षण का एक हिस्सा था, जिसमें नर्सिंग आफिसर को विभागों में जाकर काम सीखना था, लेकिन केजीएमयू नर्सेज एसोसिएशन ने इसमें नया खुलासा कर दिया है। पत्र के मुताबिक विभाग में सात दिन की ड्यूटी करने पहुंचे नवनियुक्त नर्सिंग अ फिसर कार्य करने से मना करते हैं, वह कहते हैं कि उन्हें अधिकारियों ने काम करने से मना किया है।

बहराइच में घाघरा नदी में फंसे ११४ किसानों का हुआ रेस्क्यू

बहराइच। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एक टापू पर फंसे किसानों को बचा लिया गया है। नदी के बीच फंसे किसानों को बचाने के लिए शुक्रवार शाम से ही रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा था, जो शनिवार सुबह संपन्न हुआ। दरअसल, सभी किसान घाघरा नदी के बीच अपने खेतों में काम करने के लिए गए थे। तभी घाघरा नदी में ढाई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और इसके चलते किसान वहीं फंस गए। वहीं, प्रशासन की ओर से रेस्क्यू चलाकर सभी किसानों को सुरक्षित बचा लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि सुजौली इलाके के चहलवा में वह खेती के लिए गए थे। तभी अचानक बाढ़ आ गई और वह खेतों में ही फंस गए। लेकिन बाद में उन्होंने एक टापू पर पनाह ली और प्रशासन की मदद से उन्हें बचा लिया गया। उपजिलाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग घाघरा नदी के बीच एक टापू पर फंस गए हैं। इसके बाद मौके पर एनडीआरएफ और सीमा सुरक्षा बल की टीम भेजी गई। शुक्रवार देर रात तक ६३ लोगों को बचाया गया। साथ ही ५५ लोगों को शनिवार सुबह तक निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम को चौधरी चरण सिंह बैराज से घाघरा नदी में ढाई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ११४ किसान खेती करते वक्त चहलवा में घाघरा नदी के बीच फंस गए थे। देर रात तक ६३ लोगों को

बचाया गया था, लेकिन बढ़ते जलस्तर की वजह से ५५ लोग टापू पर ही फंसे रहे। इस दौरान प्रशासन ने उन्हें वहां से निकालने के लिए एनडीआरएफ टीम और सीमा सुरक्षा बल की मदद ली। आपको बता दें कि नेपाल में पहाड़ों पर जमकर बारिश हो रही है। इसके चलते नेपाल की ओर से लगातार नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है। इसका असर नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है।

उत्तर प्रदेश में सोनम किन्नर ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन

लखनऊ। भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में स्थितियां सहज नहीं दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सोनम किन्नर ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, सरकार ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। सोनम किन्नर ने हाल ही में राज्यपाल से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके इस्तीफे की अटकलें लगने लगी थीं। सोनम किन्नर पहले समाजवादी पार्टी में थीं। सपा छोड़कर वह भाजपा में शामिल हुई थीं। सोनम किन्नर ने कहा है कि चूंकि लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है, इसलिए वह इसे अपने ऊपर लेंगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वह अब सरकार के बजाय संगठन के भीतर काम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने सरकार के अधिकारियों पर पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि सोनम किन्नर हमेशा नौकरशाही कार्यप्रणाली के खिलाफ मुखर रही हैं और उन्होंने लगातार योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। योगी सरकार ने सोनम किन्नर को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड) का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सोनम का पूरा नाम किन्नर सोनम चिश्ती है और वह कथित तौर पर अजमेर की रहने वाली हैं। सोनम कई वर्षों से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में समान दर्जा दिलाने के लिए काम कर रही हैं और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले सोनम समाजवादी पार्टी से जुड़ी थीं।

जूनियर वकीलों के प्रति सामंती सोच त्यागें, उन्हें सम्मानजनक मेहनताना दें: Chief Justice

नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अधिवक्ताओं से जूनियर वकीलों के प्रति सामंती सोच त्यागने को कहा। उन्होंने कहा कि जूनियर वकीलों को कम पैसे देने से पेशे में आने का उनका उत्साह कम हो जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के २०वें स्थापना वर्ष समारोहों का उद्घाटन करने के बाद, प्रधान न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए डेटा एवं स फ्टवेयर सामग्री के भंडार के रूप में कार्य करने में पीठ के योगदान की सराहना की। वकालत के पेशे की शुरूआत कर रहे जूनियर वकीलों को बहुत कम वेतन दिये जाने का मुद्दा उठाते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ''कृपया यह सामंती सोच त्याग दें कि वे सीखने, अवसर पाने, अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं और आप उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि जूनियर वकीलों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जूनियर वकीलों को ५,००० रुपये प्रति माह जैसी कम राशि देने से वकालत के पेशे में आने का उनका उत्साह कम कर दिया जाता है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि

जूनियर वकील मौजूदा वास्तविकताओं के प्रति विशेष रूप से अधिक जागरूक हैं तथा उन्होंने कहा कि जूनियर वकीलों को ''उनकी कड़ी मेहनत के अनुरूप सम्मानजनक राशि'' प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पर्याप्त वेतन के बिना कड़ी मेहनत का यह अति–रुमानीकरण केवल बयानबाजी नहीं है, बल्कि इससे लोगों से कम आराम और कम मेहनताने के साथ लंबे समय तक काम करने की उम्मीद की जाती है। पीठ की नवीनतम ''उल्लेखनीय उपलब्धि'' की सराहना करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने डेटा और स फ्टवेयर का नियमित रूप से रिक र्ड रखने के लिए इस वर्ष मदुरै पीठ में एक आपदा राहत केंद्र स्थापित किया है। प्रधान न्यायाधीश ने 'विगेनटेनियल स्तूप' का वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये उद्घाटन किया। यहां तामुक्कम मैदान में आयोजित समारोहों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आर महादेवन भी शामिल हुए।

आतंकियों का होगा जड़ से सफाया, मोदी सरकार ने बना लिया है तगड़ा प्लान

जम्मू। जम्मू क्षेत्र में बढ़े आतंकी हमलों ने सभी को चिंता में डाल रखा है। आतंकियों के खिलाफ लगातार सर्च अ परेशन जारी है। इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सुरक्षा स्थिति में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने एक खास अपील भी की है। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों को जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद के खतरे से लड़ने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। प्रध ानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह अपने उधमपुर संसदीय क्षेत्र के हिस्से डोडा में थे, जो पिछले तीन महीनों में कई आतंकवादी घटनाओं से दहल गया था, जिसमें १० सुरक्षाकर्मियों और एक ग्राम रक्षा गार्ड (वीडीजी) की जान चली गई थी। तीन घंटे से अधिक समय तक चलने वाले सामान्य 'सार्वजनिक दरबार' के आयोजन से पहले एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने वीडीजी के पुनरुद्धार की पुष्टि की। उन्होंने कहा, 'आतंकी घटनाओं के मद्देनजर डोडा और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के पास एक रणनीति है, लेकिन ऐसी रणनीतियों पर सार्वजनिक रूप से

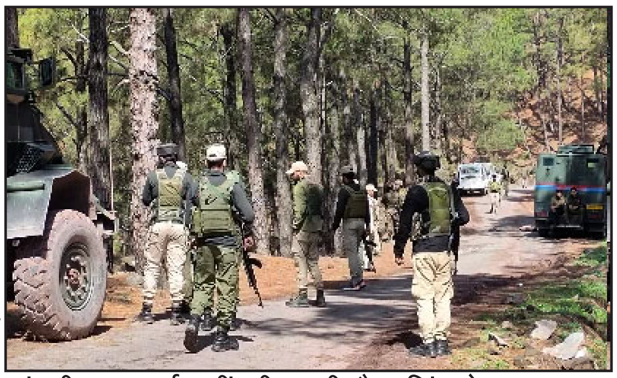

चर्चा नहीं की जाती है।' सिंह ने आगे कहा कि सरकार दुश्मन देश की गलत हरकतों से निपटने के लिए काम कर रही है। कुछ ऐसी रणनीतियां बनाई गई हैं जिनकी चर्चा सार्वजनिक तौर पर नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हमने वीडीजी (ग्राम रक्षा गार्ड) को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने मान लिया है कि...उनके हथियारों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सिंह ने घोषणा की कि वीडीजी को एसएलआर राइफल सहित हथियार उपलब्ध कराए जा सकते हैं ताकि वे चुनौती से प्रभावी ढंग से निपट सकें। मंत्री ने सभी समुदायों से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट मोर्चा खोलने की जोरदार अपील की। डोडा के बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बात करते हुए, सिंह ने कहा कि सरकार के पिछले १० वर्षों में दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा के समय को कम करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए राजमार्गों का एक नेटवर्क बनाया गया है। मंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू–कश्मीर के सभी क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने लाभार्थियों की जाति, पंथ या धर्म पर विचार किए बिना पीएम आवास के तहत एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए और घर बनाए, क्योंकि यह 'सबका साथ सबका विकास' के आदर्श वाक्य से प्रेरित है।

मंच पर सामने आया पूर्व मंत्री नारद राय का दर्द, लगाया आरोप

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री नारद राय ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मंच से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात तक प्रशासन नहीं सुनता है। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में डीएम से लेकर एसपी ऑफिस तक किसी भी काम को करने के पैसे लिए जाते हैं। यूपी में भाजपा की सरकार होने के बावजूद नारद राय के इस बयान से हंगामा बढ़ेगा। गौरतलब है कि इसके पहले भी कई नेताओं ने इस तरह के आरोप अलग–अलग जिलों में लगाए हैं। नारद राय ने कहा कि तहसील में बीजेपी कार्यकर्ताओं की लेखपाल, तहसीलदार से लेकर एसडीएम तक नहीं सुनते हैं। पुलिस और जिला प्रशासन बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करते हैं। उन्होंने कहा कि बलिया में बंदूक के साथ चाकू का भी लाइसेंस बनता है, अगर हथियार का लाइसेंस बनवाना हो तो पैसा देना पड़ता है। हालांकि नारद राय के बयान को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार या संगठन की तरफ से सामने नहीं आई है।

सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित 40 जिलों को जारी किये 120 करोड़ रुपए

लखनऊ। योगी सरकार ने बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, परिवार को राहत सहायता देने, कृषि निवेश अनुदान समेत अन्य राहत कार्यों के लिए अतिसंवेदनशील और संवेदनशील ४० जिलों को १२० करोड़ की धनराशि जारी की है। यह धनराशि योगी सरकार ने राज्य आपदा मोचक निधि से बाढ़ प्रभावित जिलों को आवंटित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से ज्यादा प्रभावित जिलों को ५ करोड़ जबकि सामान्य प्रभावित जिलों को एक–एक करोड़ की धनराशि आवंटित की है। लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोण्डा, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, बरेली, आजमगढ़, हरदोई, अयोध्या, बदायूं, फर्रुखाबाद, बस्ती, देवरिया एवं उन्नाव। महराजगंज, बिजनौर, गाजीपुर, मऊ,

अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, पीलीभीत, सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, हमीरपुर, गौतमबुद्धनगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, वाराणसी, लखनऊ एवं कासगंज।

कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने शिंदे सरकार के विरूद्ध जारी किया आरोपपत्र

मुंबई। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने शनिवार को एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ अपना 'आरोपपत्र' जारी किया और कहा कि लोग आगामी विधानसभा चुनाव में 'भ्रष्टाचार के जरिए बनी' इस सरकार को सबक सिखाएंगे। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोरात ने कहा कि वर्तमान सरकार में मुंबई और राज्य के बाकी हिस्सों में अपराध और नशीली दवाओं की तस्करी बढ़ गयी है तथा भ्रष्टाचार सभी क्षेत्रों में फैल रहा है। थोरात ने कहा, ''मानसून की पहली बारिश में मुंबई की हालत बहुत खराब हो गई है। सीवर लाइनों और नालों की सफाई में भ्रष्टाचार है। विधायकों को खरीदा जाता है। भ्रष्टाचार के जरिए बनी यह सरकार बहुत भ्रष्ट है। विधानसभा चुनाव में सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोग उन्हें सबक सिखाएंगे।'' उन्होंने कहा कि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के गठबंधन वाली इस शिंदे सरकार के शासन में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी आसमान छू रही है। यहां जिस कार्यक्रम में 'आरोपपत्र' जारी किया, वहां मुंबई कांग्रेस प्रमुख और लोकसभा सदस्य वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि इस महानगर में 'शासन से मित्रता रखने वालों को ' जमीन मुफ्त दी जा रही है एवं

उद्योग – धंधे राज्य से जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, ''हम यह आरोपपत्र जनता की अदालत में पेश कर रहे हैं। राज्य सरकार ने न केवल मुंबई के साथ अन्याय किया है, बल्कि आत्मसम्मान, पहचान और सद्भावना को भी चोट पहुंचाया है। महायुति सरकार की सत्ता में आने के बाद लड़का मित्र योजना शुरू की गई, धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहतदोस्तों के फायदे के लिए सभी नियमों में ढील दी गयी।

जेल में बंद निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह ने किया हाई कोर्ट का रुख

नई दिल्ली। कट्टरपंथी सिख उपदेशक और खडूर साहिब से सांसद (सांसद) अमृतपाल सिंह, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में बंद हैं, ने शुक्रवार (१६ जुलाई) को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया। हिरासत सहित अधिनियम के तहत उनके खिलाफ पूरी कार्यवाही को रद्द करने के निर्देश। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में कहा कि उसकी हिरासत अवैध है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि ष्प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकारों के खिलाफ मुखर होने के लिए याचिकाकर्ता को दंडित करने के अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं है, जो इस देश के प्रत्येक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है। सिंह ने याचिका में कहा कि हिरासत का आधार मुख्य रूप से दुनिया भर में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपलोड किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है, जिसका पंजाब राज्य में शायद ही कोई प्रभाव पड़ता है और संभवतः भारत राज्य की सुरक्षा इतनी नाजुक नहीं हो सकती कि सोशल मीडिया पोस्ट से प्रभावित हो। इसमें यह भी दावा किया गया कि याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को असामान्य और क्रूर तरीके से न केवल एक वर्ष से अधिक समय तक निवारक हिरासत अधिनियम लागू करके छीन लिया गया है, बल्कि उसे उसके गृह राज्य, घर, दोस्तों से दूर भी हिरासत में रखा गया है। अनावश्यक रूप से कठोर और प्रतिशोधात्मक क्योंकि उसके घर और हिरासत के राज्य के बीच की दूरी लगभग २,६०० किमी है।

चिराग पासवान को भी पसंद नहीं आया कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का फरमान

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के आदेश की आलोचना की है। भाजपा के कई अन्य सहयोगी दलों ने भी इसकी आलोचना की है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, जयंत चौधरी की रालोद के बाद अब चिराग की पार्टी की बारी है। चिराग ने मुजफ्फरनगर में पुलिस की उस सलाह पर आपत्ति जताई है, जिसमें भोजनालयों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। चिराग पासवान ने कहा कि वह पुलिस की सलाह या 'जाति या धर्म के नाम पर विभाजन' पैदा करने वाली किसी भी चीज का समर्थन नहीं करते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह सलाह का समर्थन करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष ने कहा, 'नहीं, मैं नहीं करता।' खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले पासवान ने कहा कि उनका मानना है कि समाज में दो वर्ग के लोग मौजूद हैं – अमीर और गरीब – और विभिन्न जातियों और धर्मों के व्यक्ति दोनों श्रेणियों में आते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हमें इन दोनों वर्गों के लोगों के बीच की दूरी को पाटने की जरूरत है। गरीबों के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, जिसमें समाज के सभी वर्ग जैसे दलित, पिछड़े, ऊंची जातियां और मुस्लिम भी शामिल हैं। सब वहाँ हैं। हमें उनके लिए काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी जाति या धर्म के नाम पर इस तरह का विभाजन होता है, तो मैं न तो इसका समर्थन करता हूं और न ही इसे प्रोत्साहित करता हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र

का कोई भी शिक्षित युवा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से आता हो, ऐसी चीजों से प्रभावित होता है। योगी सरकार के आदेश पर रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि गांधी जी, चौधरी चरण सिंह और अन्य महानुभावों ने धर्म और जाति को पीछे रखने की बात कही है। अब नेता राजनीति में धर्म और जाति को आगे बढ़ा रहे हैं। एएनआई के मुताबिक त्रिलोक त्यागी ने कहा कि मुझे लगता है कार्रवाई सही नहीं है। आप सड़क पर ठेलों पर किसी से अपना नाम क्यों लिखवाते हैं? उन्हें काम करने का अधिकार है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह परंपरा बिल्कुल गलत है। यह ग्राहक पर निर्भर है, वे जहां चाहें वहां से खरीदारी कर सकते हैं। मैं राजनेताओं से पूछना चाहता हूं – क्या शराब पीने से आप धार्मिक रूप से भ्रष्ट नहीं हो जाते? क्या ऐसा तभी होता है जब आप मांस खाते हैं? तो फिर शराब पर रोक क्यों नहीं है? वे शराब के बारे में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि व्यापार करने वालों की सांठगांठ है, यह ताकतवर लोगों का खेल है। ये छोटी–छोटी दुकानें गरीबों द्वारा लगाई जाती हैं। तो आप उन पर उंगली उठा रहे हैं। मैं मांग करूंगा कि शराब पर प्रतिबंध लगाया जाये। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि इससे भी बड़ी (यूपी में) कांवड़ यात्रा बिहार में होती है। वहां ऐसा कोई आदेश प्रभावी नहीं है। लगाए गए ये प्रतिबंध श्सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासश का उल्लंघन है, जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश बिहार, राजस्थान, झारखंड में प्रभावी नहीं है। इसकी समीक्षा हो तो अच्छा रहेगा। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि यूपी में कांवड़ यात्रा बड़े पैमाने पर होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता की सुरक्षा के प्रति हमेशा सजग रहे हैं।

अकबरनगर में पौधारोपण कर सीएम योगी ने ''पेड़ लगाओ–पेड़ बचाओ'' अभियान का किया शुभारंभ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे अकबरनगर में पौधारोपण करके ''पेड़ लगाओ–पेड़ बचाओ'' वृक्षारोपण अभियान २०२४ की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी एक पेड़ मां के नाम लगाने के प्रदेशवासियों से अपील की। अकबरनगर में प्रदेश सरकार की ओर से १० हजार पौधरोपण किये जा रहे हैं। जिसे अब सौमित्र वन के नाम से जाना जायेगा। इस मौके पर वन मंत्री ड अरुण कुमार सक्सेना, पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा, महापौर सुषमा खर्कवाल समेत कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से पेड़ लगाओ–पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान २०२४ के तहत शनिवार को प्रदेशभर में पौधरोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से यूपी सरकार को इस साल ३६.५० करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य दिया है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश के सभी जिलों में नोडल अधिकारी नामित किया है। वहीं यूपी सरकार के २६ विभाग वृक्षारोपण अभियान में शामिल हैं। जिन्हें प्रदेश स्तर पर पौधरोपण करने की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा प्रदेश के सभी मेयर, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानों समेत अन्य जन प्रतिनिधियों को भी अपने अपने शहरों, इलाकों, मोहल्लों और गलियों में ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करने की अपील की गई है, जिससे ३८.५० करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

अकबरनगर के विस्थापितों ने वापस मांगी अपनी जमीन

लखनऊ। लखनऊ के अकबरनगर से विस्थापित हुए लोगों ने शनिवार को वसंत कुंज में अपनी जमीन वापस करने और मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शनिवार को बड़ी संख्या में लोगों ने पोस्टर–बैनर लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई मांगें की। विस्थापित किए गए लोगो ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अकबरनगर के साथ अन्याय किया है। उनका कहना है कि पहले अकबरनगर में डूब क्षेत्र घोषित करने की नोटिस दी गई और इसके बाद बुलडोजर लगाकर सब तहस–नहस कर दिया गया। वहीं वसंत कुंज में विस्थापित किए जाने के बाद बच्चों की पढ़ाई छूट गई, लोगों का रोजगार खत्म हो गया और लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। प्रदर्शन कर रहे बच्चे, महिलाएं और पुरुषों ने कहा कि उन्हें भी पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर की तरह न्याय चाहिए। उनकी मांग है कि उन सभी को घर , जमीन और धार्मिक स्थल वापस किए जाएं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अकबरनगर में पौधारोपण करके सौमित्र वन का नाम दिया है। इसके बाद अकबरनगर से विस्थापित लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। उन्होंने इंद्रप्रस्थ नगर और पंत नगर की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। वसंत कुंज में बच्चों और महिलाओं ने मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाते हुए जमकर नारेबाजी की।

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के खिलाफ लखनऊ में मुकदमा दर्ज

कुंडा/प्रतापगढ़। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह श्राजा भैयाश्की पत्नी भानवी कुमारी सिंह के खिलाफ राजधानी के हजरतगंज कोतवाली में १२०ठ, ४१६, ४२०, ४६७, ४६८, ४६६, ४७१, ५०६ जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा द प्रॉपर्टीज कंपनी के पूर्व निदेशक आशुतोष सिंह ने दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि द प्रापर्टीज की निदेशक भानवी सिंह हैं। आशुतोष का आरोप है कि षड्यंत्र कर और दबाव बनाकर कम्पनी के निदेशक पद से उन्हें हटाया गया। आशुतोष सिंह का कहना है कि कंपनी गठन के समय से वह शेयर धारक है। उनके फर्जी हस्ताक्षर कर फ्रॉड करके कम्पनी से हटाया गया। पीड़ित के अनुसार इसकी शिकायत कानपुर के रजिस्ट्रार कार्यालय में की गई थी। आशुतोष का कहना है कि कम्पनी के शेयर में भी भानवी सिंह ने फ्रॉड किया है। पुलिस को दी तहरीर में शिकायतकर्ता आशुतोष ने बताया है कि वह प्रतापगढ़ का ही रहने वाला है, कंपनी का काम जमीन जायदाद की खरीद और बिक्री करने के साथ ही विकसित करने का भी है। उसने बड़ी ही मेहनत से कंपनी को आगे बढ़ाने का काम किया। जब कंपनी का नाम बड़ा हो गया और फायदे में आ गई तो निदेशक भानवी कुमारी के मन में लालच भी बढ़ गया। यही वजह है कि कंपनी पर एकाधिकार करने की नीयत से मेरे ऊपर बाहर जाने का दबाव डाला जाने लगा। जिसका पीड़ित लगातार विरोध कर रहा था। आशुतोष के

अनुसार यही वजह है कि षड़यंत्र के जरिये मुझे निकाला गया। इतना ही नहीं मेरी जगह पर भानवी कुमारी ने अपनी बेटी को निदेशक बना दिया है। आशुतोष ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि भानवी कुमारी जब कंपनी का गठन कर रहीं थीं, तभी से उनकी मंशा पर सवालिया निशान लग रहा था। भानवी कुमारी ने कंपनी गठन के समय अपने पति का नाम न लिखकर दस्तावेजों में अपने पिता का नाम लिखा। जबकि कार्यालय का पता अपने पति के आवास का दिया था।

पुरानी पेंशन को लेकर दो दर्जन से अधिक जगह पर हुआ प्रदर्शन

लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को करीब २५ अलग अलग जगह पर रेलवे के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। हालांकि यह प्रदर्शन सांकेतिक था, लेकिन कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन से यह जता दिया है कि पुरानी पेंशन बहाली पर ही बात बनेगी। एनपीएस को लेकर कर्मचारियों में असंतोष है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में रेलवे के हजारों कर्मचारियों ने अपने–अपने तैनाती स्थल पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। डीआरएम अ फिस और वर्कश प में हुए प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की है। उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन के शाखा मंत्री हरेंद्र सिंह भदोरिया ने बताया कि उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन सम्बद्ध भारतीय रेलवे मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ समय–समय पर कर्मचारियो की समस्याओ को प्रशासन के समक्ष उठाता रहा है, इसी के तरह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आलमबाग स्थित उत्तर रेलवे के कैरिज शाप के प्रांगण में किया गया। जिसमें एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की गई। साथ ही ८वें वेतन आयोग का गठन किया जाय, कर मुक्त आय की सीमा ८ लाख की जाय, केन्द्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना में बीमा की राशि न्यूनतम १५ लाख की जाय समेत अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन किया गया। जिसमें हरिश्चन्द्र राजभर, आशीष कुमार, विजय कुमार, कल्लू जी, देवेन्द्र सिंह, प्रदीप कुमार सहित सभी पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने यह भी कहा है कि लखनऊ, बनारस, गोरखपुर में अभी तो यह प्रदर्शन सांकेतिक था। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। तो भारतीय मजदूर संघ और भारतीय रेलवे मजदूर संघ इस पर बड़ा फैसला ले सकता है।

ड्यूटी के वक्त मोबाइल पर मशरुफ दिखे नौ पुलिसकर्मी

लखनऊ। यौम–ए–आशूरा के जुलूस को सकुशल सम्पन्न करने के लिए पुराने लखनऊ में भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया था। इसके साथ ही संयुक्त पुलिस आयुक्त ने पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद इसके नौ पुलिसकर्मी ड्यूटी के वक्त मोबाइल पर मशरुफ दिखे। समय काटने के लिए वह ड्यूटी के समय ज्यादातर मोबाइल पर व्यस्त दिखाई। इन पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर इनकी कार्यशैली की रिपोर्ट जेसीपी कार्यालय में सौंपी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं, इन पुलिसकर्मियों पर गाज गिरनी तय है। दरअसल, दसवीं मुहर्रम यानि यौम–ए–आशूरा के जुलूस को देखते हुए लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर सभी थानों से पुलिसकर्मियों को अलग–अलग स्थान पर तैनात किया था। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया था कि ड्यूटी के वक्त वह मोबाइल नहीं चलाएंगे। इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने अनुशासनहीनता की हदें पार कर दी। इसमें बीकेटी थाने में तैनात सिपाही दीपकुमार बैगर कैप के ड्यूटी पर मोबाइल में व्यस्त रहे।

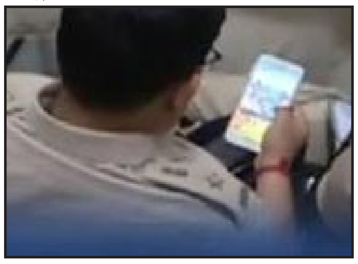

कैसरबाग कोतवाली में तैनात सिपाही कुलदीप राठौर, पारा थाने में तैनात सिपाही नरेश कुमार, मोहित, शिवेंद्र कुमार, गुडम्बा थाने में तैनात सिपाही सुशील कुमार, दलबीर सिंह, महिला सिपाही गंगोत्री देवी और गोमतीनगर विस्तार थाने में तैनात महिला सिपाही शिखा सिंह जुलूस में ड्यूटी के दौरान पर बैगर कैप के सारा दिन मोबाइल पर व्यस्त दिखीं। इन सभी पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया है। इनकी कार्यशैली की रिपोर्ट तैयार कर जेसीपी कार्यालय के अर्दली रुम में सौंपी गई है। सूत्रों की मानें तो पुलिसकर्मियों के आचरण को देखकर इन पर निलम्बन की कार्रवाई की जा सकती है। गौरतलब है कि वर्ष २०१६ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए सख्त आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी मोबाइल पर व्यस्त रहेगा, तो उसे तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाएगा। इसके बाद २०२३ में तत्कालीन पुलिस आयुक्त एसबी शिरडकर ने भी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त लहजे में आदेशित किया था कि ड्यूटी के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी मोबाइल पर समय काटता दिखाई पड़ेगा तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः इनोवेटिव लर्निंग से सीख सकेंगे पालि भाषा

लखनऊ। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में दीक्षारम्भ–कार्यक्रम के अन्तर्गत बौद्धदर्शन एवं पालि विद्या शाखा दस दिवसीय 'व्यावहारिक पालि व्याकरण शिक्षण कार्यशाला' का समापन हो गया। इस कार्यशाला में पालि व्याकरण का विविध भाषिक दृष्टियों से अध्यापन किया गया। इस अवसर पर बौद्ध दर्शन एवं पालि विद्याशाखा के संयोजक प्रो. गुरुचरण सिंह नेगी ने बताया कि पालि के व्याकरण को सरल–सहज तथा मनोरंजक ढंग से सिखाने के कारण इस कार्यशाला का उद्देश्य पूर्ण हो गया। कार्यशाला में अध्येताओं ने पालि व्याकरण को बहुत ही गहनापूर्वक सीखा तथा अब पालि ग्रन्थों को पढ़ने और समझने हेतु उनकी पृष्ठभूमि बन चुकी है। संयोजक डॉ. प्रफुल्ल गड़पाल ने बताया कि लखनऊ परिसर में एम.ए. (पालि) में किसी भी विषय में स्नातक किए हुए अध्येता प्रवेश लेते हैं। स्टूडेंट्स को पालि का व्याकरण तथा साहित्य परिचय कराना आवश्यक है। इसी दृष्टि से यह कार्यशाला आयोजित की गयी थी तथा भविष्य में इसके उच्चतर ज्ञान के साथ विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। भविष्य में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं संचालन किया जाएंगे, जिनसे व्यापक स्तर पर पालि का शिक्षण

सम्भव हो सकेगा। ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से बी.ए. तथा एम.ए. के पाठ्यक्रमों को यथाशीघ्र निर्मित करने का प्रयास चल रहा है। इस अवसर कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे विद्याशाखा के अध्येताओं ने भी अपना अनुभव सांझा किया। पालि विकास अधिकारी डॉ. जयवन्त खण्डारे तथा पालि अध्ययन केन्द्र में रिसर्च एसोसिएट डॉ. प्रियंका ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन बौद्धदर्शन एवं पालि विद्या शाखा की असिस्टेंट प्रो. डॉ. कृष्णा कुमारी ने किया। धन्यवाद ज्ञापन रामचन्द्र बौद्ध ने किया। इस अवसर पर राजेश चन्द्रा के सौजन्य से प्राप्त धम्मपद की पुस्तकों का निःशुल्क वितरण भी किया गया।

यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर जारी किए निर्देश, भड़कीं मायावती

लखनऊ। यूपी सरकार के बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर व्यापारियों के लिए निर्देश जारी किए हैं कि सभी दुकानदार अपनी–अपनी दुकानों के बोर्ड पर मालिक और स्टाफ के नाम के साथ पूरी पहचान लिखनी होगी। इसके साथ ही मांस बिक्री पर भी रोक लगाने की बात भी कही गई है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर 'नेमप्लेट' को अनिवार्य कर दध्यिा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से शुक्रवार को जानकारी दी गई कि कांवड़

यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर बसपा प्रमुख मायावती ने सोसल मीडिया मंच एक पर के जरिए कहा कि यूपी व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कांवड़ मार्ग के व्यापारियों को अपनी–अपनी दुकानों पर मालिक व स्टाफ का पूरा नाम प्रमुखता से लिखने व मांस बिक्री पर भी रोक का यह चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकाट करने का प्रयास अति–निन्दनीय।

कारगिल विजय दिवस की २५वीं वर्षगांठ पर एनसीसी कैडेट्ट्स ने मनाया कारगिल विजय दिवस

लखनऊ। कारगिल विजय दिवस की २५वीं वर्षगांठ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के नवीन परिसर में एनसीसी ग्रुप और विश्वविद्यालय के सहयोग से बृहद पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसका विषय 'एक कैडेट एक पेड़ पहल' था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय थे। लखनऊ एनसीसी ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा के नेतृत्व और ६४ यूपी बटालियन एनसीसी एलयू के कुशल समन्वयन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति, चीफ प्रॉक्टर, डीन एकेडामिक, कार्य अधीक्षक, द्वितीय परिसर के निदेशक और अन्य शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। ६४ यूपी बटालियन, ६३ यूपी बीएन, ३ यूपी नेवेल, ५ यूपी एयर और २० गर्ल्स बीएन के लगभग २५० कैडेट्स ने वृक्षारोपण किया। इस बृहद पौधरोपण में विभिन्न एनसीसी बटालियन के कमान अधिकारीयों, जेसीओ, एनसीओ उपस्थित रहे। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के सभी एसोसिएट

एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर (प्रो.) डीके सिंह, मेजर (डॉ.) किरन लता डंगवाल, डॉ. रजनीश कुमार यादव, ग्राउंड एंड गार्डेन के डायरेक्टर और उनकी पूरी टीम उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान सभी ने पौधरोपण कर कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजली दी और स्वस्थ पर्यावरण की तरफ एक नई पहल की शुभकामनायें दी।

बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर सरकार ने मांगा स्पष्टीकरण

लखनऊ। शासन ने डिग्री कॉलेजों से बायोमेट्रिक मशीन की उपलब्धता से लेकर हाजिरी का ब्योरा संबंधित विश्वविद्यालयों और महाविद्यालय प्रबंधन से मांगा है। जारी पत्र में तत्काल सूचना देने के निर्देश भी स्थानीय उच्च शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी किये हैं। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार का कहना है कि सभी सरकारी और अनुदानित महाविद्यालयों को पत्र जारी किया है। इसमें कॉलेजों से तीन बिन्दुओं पर सूचना भेजने के निर्देश दिए हैं। कॉलेज प्रबंधन/प्राचार्य से पूछा गया है कि क्या शिक्षक, शिक्षणेत्तर एवं छात्र–छात्राओं के लिए महाविद्यालय में बायोमेट्रिक मशीन लगाई गई है। यदि हां, तो क्या महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक, शिक्षणेत्तर एवं छात्र–छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज की जा रही है। अगर नहीं, तो बायोमेट्रिक मशीन नहीं लगाये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने कहा कि लखनऊ के अलावा अयोध्या, अंबेडकरनगर, गोंडा, लखीमपुर, बहराइच, अमेठी, सुलतानपुर, सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली के ऐसे महाविद्यालयों की एक सूची भी जारी की गई है, जिनकी बायोमेट्रिक हाजिरी की सूचना अब तक मिली है। ३७ कॉलेजों को मिला पत्र क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी ३७ क लेज की सूची में लखनऊ के आठ अनुदानित क लेज भी शामिल है। इसमें नेशनल डिग्री कॉलेज, आईटी कॉलेज, महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज, बप्पा श्रीनारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज और मुमताज डिग्री कॉलेज सम्मिलित है। लखनऊ विश्वविद्यालय सहयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) बायोमेट्रिक हाजिरी विरोध करेगा। अगर जरूरत पड़ी, तो प्रदर्शन भी किया जाएगा।– डॉ. मनोज पांडेय, लुआक्टा

झोपड़ी में घुसा बेकाबू ट्रक, एक ही परिवार के ४ लोगों की मौत

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी के पास भीषण हादसा हो गया है। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई है। मृतक परिवार बाराबंकी का रहने वाला बताया जा रहे है। मृतकों में पति, पत्नी और उनके दो बच्चे शामिल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया और आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद घटना की जांच शुरू कर दी है। दरअसल, एक अनियंत्रित ट्रक बेकाबू होकर झोपड़ी में जा घुसा। उसमें सो रहे एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक सात वर्षीया बच्ची बच गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक और क्लीनर को पकड़ लिया गया है।

१० विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने लिया फीडबैक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में १० विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपने आवास पर बैठक की। इस बैठक में कई मंत्री शामिल हुए। चुनाव में सीटवार मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी मंत्रियों को प्रभार वाले क्षेत्र में हफ्ते में दो दिन रात्रि विश्राम करना होगा। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति आदि पर चर्चा की गई। सभी १० सीटें जीतनी हैं। इसी कारण विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अपने प्रभारी क्षेत्र में जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाएं, दो दिन–रात्रि विश्राम के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी प्रभारी मंत्रियों

को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है और सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने में करना है। हर सीट पर तीन–तीन मंत्रियों के अलावा संगठन से एक–एक पदाधिकारी की तैनाती की गई है। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव में नौ विधायकों के सांसद बनने के बाद रिक्त हुई कटेहरी, मिल्कीपुर, करहल, फूलपुर, मझवां, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी और खैर सीटों के अलावा कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इनमें से करहल, कुंदरकी, कटेहरी, मिल्कीपुर और सीसामऊ सीट पर सपा काबिज रही है। जबकि, फूलपुर, खैर और गाजियाबाद सीट भाजपा के पास थी। मीरापुर की सीट पर भाजपा की सहयोगी दल रालोद तथा मझवां की सीट पर निषाद पार्टी को जीत मिली थी।

मुझे लगा था 'कल्कि २८९८ एडी' मेरी आखिरी फिल्म होगी : नाग अश्विन

मुंबई। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जानेमाने निर्देशक नाग अश्विन का कहना है कि जब वह कल्कि २८९८ एडी बना रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि यह उनकी अंतिम फिल्म होगी। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित, कल्कि २८९८ एडी में अमिताभ बच्चन, कमल हसन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी सहित कई शानदार कलाकार हैं। 'कल्कि २८९८ एडी' वर्ल्डवाइड १००० करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। श्कल्कि २८९८ एडीश के निर्देशक नाग अश्विन ने बताया है कि उन्हें लग रहा था ये उनकी आखिरी फिल्म होने वाली है। श्कल्कि २८९८ एडीश के मेकर्स वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो शेयर किया,जिसमें अमिताभ बच्चन, नाग अश्विन से खास बातचीत करते नजर आ रहे हैं। नागअश्विन ने बताया, मुझे लगा था कि कल्कि २८९८ मेरी आखिरी फिल्म होगी जो मैं बना पाऊंगा। मेरे पास एक छोटी कहानी थी, जो इसके जितनी एम्बिशियस नहीं थी, लेकिन फिल्म श्महानतीश के बाद मुझे अचानक से इंटरनेट पर इस तरह के आर्टिकल या वीडियो खूब दिखने लगे जिनमें

चिरंजीवियों के बारे में लिखा गया था। मुझे कुछ ऐसे आर्टिकल भी दिखे कि ब लीवुड में कुछ प्रोडक्शन हाउस महाभारत पर बेस्ड इस तरह की कहानियों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगा शायद अब इस कहानी को बक्से से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। अश्वत्थामा के श्राप वाली पूरी चीज कुरुक्षेत्र में पांडवों की जीत के लगभग १८ दिन बाद हुई थी। यह महाभारत में हुई लगभग सबसे अंतिम चीज थी, और ये मुझे लगा कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महाभारत में अश्वत्थामा को श्राप मिलता है और वो जंगलों में चले जाते हैं। एक व्यक्ति जो उस काल के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक है और इस पूरे कलियुग में इतनी घटनाओं के बावजूद वो मौजूद तो है, लेकिन किसी चीज में दखल नहीं दे रहा, यानी उसके पास कोई बहुत बड़ा मकसद है, जिसके लिए उसने खुद को बचा रखा है, तो मुझे लगा ये मेरा एक दुस्साहस है कि मैं ऐसी कहानी कहना चाह रहा हूं जिसे महाभारत में अधूरा छोड़ा गया है।मुझे लगा कि किसी ने अभी तक इस कहानी को छुआ नहीं हिया तो मुझे ट्राई तो करना ही चाहिए।सबसे महानतम योद्धाओं में से एक का पुत्र, जो भगवान शिव के एक रूप जैसा है... और ये न जान पाना कि उसकी कहानी में आगे क्या हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता!

स्कूलों में मनाया जाएगा शिक्षा सप्ताह

लखनऊ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–२०२० के चार साल पूरे होने पर प्रदेश के सभी परिषदीय प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालयों समेत कम्पोजिट तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षा सप्ताह मनाया जायेगा। इसके लिए २२ से २८ जुलाई का समय निर्धारित किया गया है। गुरुवार को स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में महानिदेशक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० (एनईपी) के चार साल पूरे होने पर २२ से २८ जुलाई तक स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किये गये

परिवर्तनकारी सुधारों को लेकर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। शिक्षा सप्ताह का उद्देश्य विद्यार्थियों व शिक्षकों के बीच सहयोग और नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है तथा नीति निर्माताओं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न हितधारकों की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। शिक्षा सप्ताह के दौरान अलग–अलग दिनों में कला व कौशल समेत अन्य प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। कार्यक्रम आयोजन की फोटो भी साझा करने के निर्देश दिए गये हैं।

योगी की बैठक में शामिल नहीं हुए केशव प्रसाद मौर्य

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को प्रयागराज में थे लेकिन वहीं पर हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक की जानकारी के

बावजूद वे कौशाम्बी चले गए। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच खींचतान की खबरें आ रही है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य कई बार कह चुके हैं कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को राज्य सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे की शादी से जुड़े समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। इस शादी में हिस्सा लेने के लिए ही मुख्यमंत्री भी प्रयागराज में थे। बाद में मुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और कई मंत्रियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य के प्रयागराज पहुंचने पर पत्रकारों ने सरकार और संगठन में खींचतान के बारे में पूछा तो केशव उन्होंने कहा– कुछ नहीं, कोई अफवाह नहीं है६ न्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य के थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भी प्रयागराज पहुंचे और सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। केशव प्रसाद बैठक में शामिल नहीं हुए। वे योगी के प्रयागराज पहुंचने से पहले ही कौशाम्बी के लिए निकल गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने महाकुंभ की तैयारियों के बारे में चर्चा की। इसमें गृह विभाग के प्रमुख सचिव, सूचना विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त सहित कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस से मंत्री नंदगोपाल नंदी के साथ उनके घर पहुंचे।

फिल्म 'बैड न्यूज' की शानदार ओपनिंग देख खुश हैं विक्की कौशल

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल अपनी फिल्म 'बैड न्यूज' की शानदार ओपनिंग देख खुश हैं। आनंद तिवारी के निर्देशन में बनी तृप्ति डिमरी, विक्की कौशल और एमी विर्क की फिल्म 'बैड न्यूज' १६ जुलाई को सिनेमाघरों

में रिलीज हो चुकी है। 'बैड न्यूज' ने पहले दिन भारतीय बाजार में आठ करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है। प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, विक्की कौशल ने एक वीडियो जारी किया और फैंस को प्यार के लिए धन्यवाद दिया। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर विक्की ने एक वीडियो शेयर किया। विक्की ने वीडियो साझा कर लिखा, इस तरह के प्यार के लिए, 'हम कहना चाहेंगे शुक्रिया मेहरबानी करम'। अभी अपने टिकट बुक करें! बैड न्यूज आपके नजदीकी सिनेमाघरों में चल रही है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
l t ; ckt ib
lhrkiqj
ek-9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
lj'k ukjk;.k feJ
क्षेत्रीय सम्पादक
lkjHk dqekj] fcgkj
ek-09386075289
मो० अरशद
C;jk phQ
eऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक